(c) whether Government are aware of any such group which has entered into Indian territory so far; and

(d) if not, what preventive pre-emptive steps have been taken to thwart the entry of militants in the country?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S.B. CHAVAN): (a) to (d) Certain reports indicating such activities have been received. However, Govt. is fully alive to the situation and is keeping a close watch. All necessary steps. including gearing up of intelligence and sharing of information about the movements of militant groups, are being taken. The concerned State Governments have been duly sensitised to counter possible designs of militants and maintain a hightened degree of alertness.

सड़क, जहाजरानी और बन्दरगाहों के रख-रखाव हेतु परियोजनाएं

153. **श्री राम जेठमलानी:**
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में सड़क, जहाजरानी तथा बन्दरगाहों के रख-रखाव को बेहतर बनाने संबंधी अनेक परियोजनाएं सरकार द्वारा निर्माणाधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, 1995 की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सड़क, जल-मार्गों और बन्दरगाहों से संबंधित उन परियोजनाओं की अलग-अलग संख्या कितनी है जो निजी क्षेत्र द्वारा निर्माणाधीन हैं, और

(घ) उपरोक्त परियोजनाओं में से कितनी परियोजनाएं अपने पूर्व-निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं और सरकारी व गैर-सरकारी क्षेत्र की इन परियोजनाओं की अलग-अलग संख्या कितनी है, तथा निर्माण में देरी होने के कारण इन परियोजनाओं की निर्माण लागत में कम से कम और अधिक से अधिक कितने-कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) जी, हां।

(ख) सरकार सड़क क्षेत्र में 17 बड़ी परियोजनाओं, पत्तन क्षेत्र में 15 बड़ी परियोजनाओं और अन्तर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र में 3 बड़ी परियोजनाओं का निर्माण कर रही है।

(ग) पत्तन क्षेत्र में 12 परियोजनाओं, भूमि तथा तटीय क्षेत्र सहायक सुविधाओं के विकास के लिए निजी उद्यमियों को पट्टे पर दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर कोई परियोजना निजी क्षेत्र के निर्माणाधीन नहीं है।

(घ) उक्त (ख) में उल्लिखित 35 परियोजनाओं में से सड़क क्षेत्र में 12 परियोजनाएं और सार्वजनिक क्षेत्र में पत्तन क्षेत्र की 5 परियोजनाएं अपनी पूरा होने की मूल लक्षित तारीख से पिछड़ रही है। इनके पूरा होने में विलम्ब होने के कारण इन परियोजनाओं के निर्माण की लागत में वृद्धि का प्रतिशत 16% से 145% के बीच है।

दिल्ली परिवहन निगम (डी०टी०सी०) की बसों का लाया जाना

*154. **श्री दिग्विजय सिंह:**
श्री सत्य प्रकाश मालवीय:

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जून, 1995 तक दिल्ली परिवहन निगम की कितनी बसें सड़कों पर चल रही थीं तथा कितनी बसें मामूली और बड़ी खराबियों के कारण नहीं चल रही थीं;

(ख) क्या सरकार इन सभी बसों को पुनः सड़क पर उतारने/चालू करने के लिए निगम को धन उपलब्ध कराने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने समय में कितनी बसें मरम्मत के पश्चात् सड़कों पर पुनः चलने लगेंगी; और

(घ) क्या सरकार निगम को धनराशि उपलब्ध कराने के अलावा यह सुनिश्चित करेगी कि यह धन केवल उपरोक्त मरम्मत कार्य पर ही खर्च हो?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) दिनांक 30.6.95 की स्थिति के अनुसार दि०प०नि० के पास 3481 बसों का बेड़ा था। इन 3481 बसों में से 1391 बसें प्रचालन कर रहीं थीं

और शेष 2090 बसें बड़ी/छोटी मरम्मत, टायरों, पुर्जों/असेम्बली की कमी के कारण विभिन्न वर्कशापों में खड़ी थीं जिनमें 348 बसें (कुल बेड़े का 10%) ऐसी थीं जिन्हें विभिन्न स्तरों की सामान्य/निवारक रख-रखाव, दैनिक आधार पर ब्रेक डाउन मरम्मत, एम०वी०आई० तैयार करने तथा अन्य डाकिंग आदि के लिए विभिन्न डिपुओं में खड़ा किया हुआ था।

(ख) और (ग): जी हां। सरकार ने निधियां जारी करने की तारीख से दो महीने के भीतर 1000 बसों को सड़क पर लाने के लिए 10 करोड़ रु० प्रदान किए हैं। 6.50 करोड़ रु० पहले की दिनांक 14.7.95 को दिए जा चुके हैं और शेष राशि को शीघ्र ही दिया जा रहा है।

(घ) 10 करोड़ रु० की राशि बसों को तुरंत सड़क पर लाने के लिए आवश्यक टायरों, बैटारियों और पुर्जों की खरीद के लिए जारी की गई थी। दि०प०नि० को "रिलीज आर्डर" में उल्लिखित प्रयोजन के लिए निधियों का उपयोग करने का निदेश दिया गया था।

Formation of Uttrakhand State

*155. SHRI INDER KUMAR GUJRAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a delegation of Uttarakhand Kendriya Sanyukta Sangharsh Samiti (UKSSS) has met the Prime Minister recently regarding formation of Utarakhand State;

(b) whether the delegation has been assured of an early action in this matter; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S.B. CHAVAN): (a) to (c) Yes, Sir. Though no specific assurance was given to the delegation, it is felt that no definite time frame can be fixed for finding an acceptable solution to a sensitive issue like Uttarakhand.

Land Acquired by Konkan Railway Corporation in Karnataka

*156. SHRI GUNDAPPA KORWAR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the total acres of land in Karnataka made available to the Konkan Railway Corporation for the purpose of laying tracks;

(b) the total area of the land acquired in Kannadigas region; and

(c) whether Government intend to give jobs to Kannadigas whose lands had been acquired by the Corporation?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) and (b); 3724.54 acres.

(c) Konkan Railway is following the guidelines laid down by the Government to offer employments to one ward of a family provided the family has lost the sole means of livelihood on account of such acquisition of land.

Establishment of South-Western Railway Zone at Bangalore

*157. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have taken decision to establish a South Western Railway Zone at Bangalore;

(b) if so, from when the zone will start functioning; and

(c) which divisions will be transferred to this zone from Southern Railway, South Central Railway and Western Railway?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIFE): (a) to (c) The study group which had been constituted for examining the existing geographical distribution of zones and divisions in the wake of Project Unigauge and the construction of Konkan Railway,